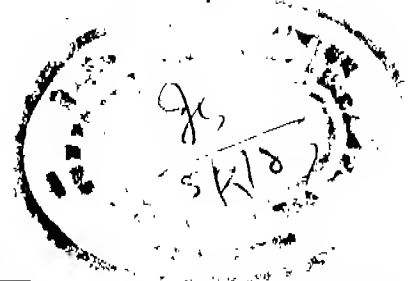




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 606]  
No. 606]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 1986/अग्राहायण 28, 1908  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 1986/AGRAHAYANA 28, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन को रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

कामिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कामिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1986

अधिसूचना

सा. का. नि. 1296 (प्र):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परम्पु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों (समूह "क" और "ग") में अधिशिष्ट कर्मचारियों के पुनराभिनियोजन का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा और पद (समूह "क" और "ग") अधिशिष्ट कर्मचारियों के पुनराभिनियोजन नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "प्रकोष्ठ" से कामिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कामिक और प्रशिक्षण विभाग में केन्द्रीय (अधिशिष्ट कर्मचारी) प्रकोष्ठ अभिप्रेत है ;

(ख) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "अधिशिष्ट कर्मचारियों" और "अधिशिष्ट कर्मचारी" से ऐसे केन्द्रीय सिविल सेवा (तथ्य, आकस्मिक, निर्धारित कर्म या

सिविल सेवा के आधार पर नियोजित में भिन्न) अभिप्रेत हैं जो केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से (रेल बोर्ड के मुख्यालय के स्थापन को छोड़कर रेल मंत्रालय से भिन्न और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से भिन्न रक्षा मंत्रालय की निम्नतर क्षेत्र विवरणों को छोड़कर)।

(i) प्रशासनिक सुधार ;

(ii) वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एड्डा द्वारा किए गए अध्ययनों ;

(iii) सरकारी विभागों या कार्यालयों द्वारा किए गए कार्य माता माध्यमों या प्रशासनिक सुधारों ; और

(iv) केन्द्रीय सरकार के स्थायी या दीर्घकालीन संगठनों के उत्पादन या परिसमापन के कारण अधिशिष्ट हो गए हैं ;

परम्पु विनिश्चित प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से स्थापित किसी संगठन के कर्मचारियों की वशा में वे इस नियम के प्रयोजनों के लिए सभी अधिशिष्ट कर्मचारियों या अधिशिष्ट कर्मचारी माने जाएंगे यदि वह संगठन 15 वर्षों की अधिक अवधि के लिए अस्तित्व में रहा हो और उन्होंने इस संगठन में कम से कम 5 वर्षों की लगातार सेवा की हो।

3. आयोग के माध्यम से अधिशिष्ट कर्मचारियों के पुनराभिनियोजन :—

(1) समूह "क" या समूह "ग" सेवा/पद का जिसमें कोई रिक्ति आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (प्रतियोगिता परीक्षा के आधार से अन्यथा) भरी जानी है, नियंत्रक प्राधिकारी आयोग को इस प्रयोजन के लिए अध्ययन सेजते समय उसकी एक प्रति प्रकोष्ठ को भी भेजेगा।

(2) (i) आयोग इस प्रयोजन के लिए भेजी गई किसी अध्यक्षता को तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक उसने यह दृष्टि न होता हो कि उसकी एक प्रति साथ ही प्रकोष्ठ को भेज दी गई है और आयोग को अधिसूचित पदों पर भर्ती के लिए प्राथिक रीति से तब कार्यवाई करेगा यदि—

(क) उसे अध्यक्षता की आगे कार्यवाही में प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर ऐसी रिक्ति या रिक्तियों में नियोजन के लिए कार्य से अधिशिष्ट कर्मचारी/कर्मचारियों का प्रयोजन करने वाली सिफारिश प्राप्त नहीं होती है या,

(ख) विचार किए जाने के लिए प्रकोष्ठ द्वारा सिफारिश किया गया अध्यक्षीय प्रस्ताव पर पर नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा उपयुक्त नहीं पाया जाता है।

(ii) आयोग किसी अधिशिष्ट कर्मचारी पर, जिसका जीवन वृत्त प्रकोष्ठ द्वारा उसे निर्दिष्ट किया गया है, उन पद पर नियुक्ति के लिए विचार कर सकेगा। भजे हो प्रकोष्ठ द्वारा उसकी उस पद के लिए विनिर्दिष्ट रूप से सिफारिश न की गई हो :

परन्तु यह तब तब निम्नलिखित तारीखों के बीच या वेतनमान का अधिकतम नहीं है जो उसने द्वारा धारित पद का है; वह अन्य पदों के, जिसके लिए उसने अध्यक्षता प्रकोष्ठ द्वारा प्रायोजित की गई हो, अधिमान में ऐसे पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है ; और वह इस नियम के उपनिबन्ध (5) के खंड (ग) में वर्णित आशयताओं से प्रस्त नहीं है।

(3) जहाँ कोई पद आयोग के परामर्श से स्थानांतरण द्वारा भरा जाता है वहाँ पद की वास्तविक नियंत्रक प्राधिकारी पहले रिक्ति प्रकोष्ठ को सूचित करेगा जो यदि उसकी नामावली में कोई अधिशिष्ट कर्मचारी है जो उस पर नियुक्ति के लिए प्रथम अवस्था उपयुक्त है, उसे प्रस्तावित पद में आमेलन के लिए विचार किए जाने के लिए आयोग को प्रायोजित करेगा। ऐसा पद तभी परिचालित किया जाएगा यदि (क) प्रकोष्ठ उसमें आमेलन के लिए प्रायोजित करने के लिए अपनी नामावली में से उपयुक्त किसी अधिशिष्ट कर्मचारी की अनुपलब्धता संतुष्ट करता है, या (ख) आयोग प्रकोष्ठ द्वारा प्रायोजित अधिशिष्ट कर्मचारी को उस पद पर नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त अधिनिर्धारित करता है।

(4) प्रकोष्ठ द्वारा सिफारिश किए गए अधिशिष्ट कर्मचारी आयोग के माध्यम से संघों भर्ती द्वारा या स्थानांतरण पर समूह "क" और "ख" सेवाओं/पदों में रिक्तियों पर (आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार से अन्यथा) नियुक्ति के लिए प्रथम अवस्था के हकदार होंगे :

परन्तु यह तब जब कि वे आयोग द्वारा उपयुक्त पाए जाते हैं और ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उस के पास कोई उपयुक्त अगस्त सेवा कार्मिक उपलब्ध नहीं है।

(5) (क) प्रकोष्ठ किसी ऐसे अधिशिष्ट कर्मचारी के नाम की जो तत्समय उसकी नामावली पर है, किसी विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्ति के लिए, जिसमें रिक्ति आयोग और प्रकोष्ठ को अधिसूचित की गई है, और जिस पर नियुक्ति के लिए संबंध अधिशिष्ट कर्मचारी उस पद के और उसके द्वारा धारित पद के वेतनमान, उसकी प्रवृत्तियों और उसके पूर्व अनुभव की संतुष्टता को देखते हुए प्रकोष्ठ का प्रथम दृष्टता उत्तुता प्रतीत होता है, आयोग सिफारिश करेगा ;

(ख) प्रकोष्ठ अपनी नामावली में से एक से अधिक कर्मचारियों की किसी पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की सिफारिश कर सकेगा जिन्हें वह अपने से अधिक उसकी नियुक्ति के लिए प्रथम या उपयुक्त प्रतीत होता है ;

(ग) प्रकोष्ठ द्वारा अधिशिष्ट कर्मचारी के नाम को आयोग को सिफारिश नहीं करेगा—

(i) यदि प्रकोष्ठ द्वारा प्रायोजित किए जाने पर आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में उसके विद्यमान वेतनमान से अतिन्तः वेतनमान जाने पर पर नियुक्ति के लिए उसकी पहले ही सिफारिश की जा चुकी है ;

(ii) यदि उसने प्रकोष्ठ को नामावली में छह मास की अवधि पूरी कर ली है; या इसी दौरान उसने किसी अन्य पद का कार्यभार चाहे प्रकोष्ठ के माध्यम से पुनराभिनियोजन पर या अन्यथा संभाल लिया है या उसने किसी अन्य सतत पद पर, जिस पर वह कार्यवाहिकार रखता है, प्रत्यावर्तन के लिए अनुरोध किया है ;

(iii) यदि प्रकोष्ठ की नामावली पर उसके प्रस्तर्ण की तारीख से छह मास के भीतर अधिवर्धिता प्राप्त कर लेगा ;

(iv) यदि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं या उसे सेवा-निवृत्त (जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ अधिशिष्ट कर्मचारी द्वारा की गई समयपूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रार्थना का सूचना पर सेवानिवृत्ति है) या सेवानिवृत्त किया जाना है या वह प्रकोष्ठ की नामावली में उसके प्रस्तर्ण की तारीख से छह मास की समाप्ति के पूर्व किसी दिन को प्रकोष्ठ की नामावली पर नहीं रह जाता है ;

(v) नियम 5 में अधिशिष्ट श्रेणियों के परिधि के बहार जाने वाले किसी पद में आमेलन के लिए।

(vi) किसी अधिशिष्ट कर्मचारी की उपयुक्तता का अवधारण और इस प्रयोजन के लिए अर्हताओं, अनुभव आदि का शिथिलीकरण :

(क) आयोग, किसी अधिशिष्ट कर्मचारी पर पहले लिखा गई गोपनीय रिपोर्ट स्वविवेकानुसार देख सकेगा या यदि आवश्यक हो, तो किसी पद पर नियुक्ति के लिए उसकी उपयुक्तता का अवधारण करने के लिए उसे साक्षात्कार के लिए बुला सकेगा किन्तु इस प्रयोजन के लिए उसका लिखित परीक्षा नहीं होगा।

(ख) आयोग किसी सेवा/पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव आदि को प्रकोष्ठ द्वारा ऐसा सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए प्रायोजित अधिशिष्ट कर्मचारी के किसी सदस्य का वास्तविक स्वविवेकानुसार तब शिथिल कर सकेगा यदि वह अधिशिष्ट अध्यक्षीय प्रस्ताव सेवा/पद के लिए उसके द्वारा अन्यथा उपयुक्त समझा जाता है।

(ग) आयोग किसी पद के लिए प्रकोष्ठ द्वारा सिफारिश किए गए किसी अधिशिष्ट कर्मचारी की उपयुक्तता या अन्यथा का निर्धारण और उसकी संतुष्टता प्रकोष्ठ की अपने कार्यालय में ऐसी सिफारिश की प्राप्ति की तारीख से यथावत एक मास के भीतर करेगा।

स्पष्टीकरण: इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, कोई अधिशिष्ट कर्मचारी उस तारीख से, जिसकी वह अपने मूल मंत्रालय/विभाग द्वारा उपयुक्त नियम 2 के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट आकस्मिकताओं में अधिशिष्ट घोषित किया गया है, चाहे औपचारिक रूप से वह ऐसे स्थानांतरित न किया गया हो और केवल उसकी विनिर्दिष्ट प्रकोष्ठ की रिपोर्ट की गई हो, उसके पुनराभिनियोजन की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए प्रकोष्ठ की नामावली की स्थानांतरित/उत्तम में विनिर्दिष्ट समझा जाएगा।

4. आयोग के माध्यम से न भरे जाने वाले पदों में पुनराभिनियोजन :

(i) केन्द्रीय सिविल सेवाओं में सभी रिक्तियों और समूह "क" और "ख" में पद जो संघी भर्ती द्वारा या स्थानांतरण द्वारा किन्तु आयोग के माध्यम से अन्यथा भरे जाने हैं अधिशिष्ट

कर्मचारियों में से घरे जायेंगे जब तक कि प्रयोजन सेवा/पद के निम्नतम प्राधिकार में प्रकोष्ठ से यह प्रतिनिधित्व नहीं कर लिया हो कि उनके पास उपलब्ध अधिशिष्ट कर्मचारियों में से उस विशिष्ट पद के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है।

(2) उपनियम (1) में किए गए उपबंध—

(क) (i) परमाणु उर्जा, (ii) प्रतरिष्ठा, (iii) इलेक्ट्रॉनिक्स, (iv) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा, और (v) रेल (रेल बोर्ड के मुख्यालय कार्यालयों में पदों की सोझकर) विभाग;

(ख) रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से भिन्न) निम्नस्तर सेक विरचनाएं;

(ग) गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधीन

विभिन्न सुरक्षा और प्रशंसीनिक संगठनों, के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पदों और सेवाओं की लागू नहीं होंगी।

परन्तु इससे ऐसे सेवाओं/पदों का निम्नतम प्राधिकारी उपयुक्त अधिशिष्ट कर्मचारियों के प्रयोग के लिए प्रकोष्ठ को अनुरोध करने और उन्हें नियुक्त करने से विवर्जित नहीं होगा।

(3) उपनियम (1) के अर्थान नाम निदिष्ट अधिशिष्ट कर्मचारियों की बाबत क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग और उप नियम (2) के अन्तर्गत प्रायोजित कर्मचारियों की बाबत संबद्ध मंत्रालय/विभाग संगठन संबद्ध पदों पर नियुक्ति के लिए उनकी उपयुक्तता का अवधारण जहाँ आवश्यक हो, सुसंगत भर्ती नियमों के अर्थान विहित शैक्षणिक महत्ताओं, अनुभव आदि का विनिर्देशन करके, करेगा।

5. कर्मस्थान का अवधारण—(क) (i) कोई अधिशिष्ट कर्मचारी, उसका उपयुक्तता के अधीन रहते हुए, यथासंभव ऐसे पद में पुनराभिनियोजित किया जाएगा जिसका वेतनमान उसके वर्तमान वेतनमान से तुलनाय है।

(ii) खंड (i) के प्रयोजनों के लिए तुलनीय वेतनमान से वह वेतनमान अभिवेद होगा जिसका अधिकतम अधिशिष्ट कर्मचारी के वेतनमान के अधिकतम के बराबर है और जिसका न्यूनतम मूल वेतन में (जिसे प्रतगत वृद्धि कृत्र वेतन है) जो अधिशिष्ट कर्मचारी अपना नाम निर्देशन किए जाते समय प्राप्त कर रहा है, अधिक नहीं है।

(ख) जहाँ तुलनीय वेतनमान वाला कोई उपयुक्त पद उपलब्ध नहीं है वहाँ अधिशिष्ट कर्मचारी किसी अनुतुलनीय वेतनमान वाले पद पर पुनराभिनियोजित किया जा सकेगा।

परन्तु यह तब जब कि—

(i) ऐसे पद के वेतनमान का अधिकतम अधिशिष्ट कर्मचारी के वेतनमान के अधिकतम से 10% से अधिक नहीं है; और

(ii) ऐम द उस पद से निम्नतर नहीं है जो अधिशिष्ट कर्मचारी द्वारा तत्समय धारित पद के स्तर वाले पदधारियों के लिए औपस्थाधिक सोपान में आगामी निम्नतर पद है या सामान्यतया आगामी पद होगा।

परन्तु यह और कि जब अधिशिष्ट कर्मचारी किसी निम्नतर वेतनमान वाले पद पर पुनराभिनियोजित किया जाए तो उसे उसके अगले पद पर भी अपने पूर्व वेतनमान पर कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा चाहे वह उस पद पर स्थापना रूप से कार्य कर रहा हो।

6. आयु-सीमा: उपर्युक्त आयु-सीमा इन नियमों के अधीन नियुक्त किसी अधिशिष्ट कर्मचारी की वया में लागू नहीं होगी।

7. चिकित्सीय परीक्षा: प्रकोष्ठ द्वारा पुनराभिनियोजित अधिशिष्ट कर्मचारियों से नए सिरे से चिकित्सीय परीक्षा करवाने की अपेक्षा नहीं

की जाएगी जब तक कि प्राप्तकर्ता संगठन में पद के लिए भिन्न चिकित्सीय मान विहित किए गए हैं या जब तक कि संबद्ध व्यक्ति को उसके पूर्व पद के लिए चिकित्सीय परीक्षा न हुई हो या यदि हो गई हो तो उसे चिकित्सक दृष्ट्या प्रयोग्य घोषित किया गया हो।

8. भाषण द्वारा नियुक्ति के लिए विस्तारित किए गए या प्रकोष्ठ द्वारा नाम निदिष्ट अधिशिष्ट कर्मचारियों को

स्वीकार करना: प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग किसी अधिशिष्ट कर्मचारी को किसी ऐसे पद/विभाग पर नियुक्ति के लिए जिसके लिए यथास्थिति भाषण या प्रकोष्ठ से पहले अपेक्षा की गई थी भाषण द्वारा की गई सिफारिश या प्रकोष्ठ द्वारा किए गए नामनिर्देशन की प्राप्ति पर संबंध अधिशिष्ट कर्मचारी की नियुक्ति के आदेश जारी करने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा और उसकी सूचना प्रकोष्ठ को और जहाँ सुसंगत हो, आयोग को देगा।

9. वेतन और श्रेष्ठता का नियत किया जाना, विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए पूर्व सेवा की गणना और धारणाधिकार/वर्गीकरण का प्रयत्न— अधिशिष्ट कर्मचारी का नए पद में, जिस पर वह इन नियमों के अर्थान पुनराभिनियोजन पर नियुक्त किया जाता है, श्रेष्ठता और वेतन का नियत किया जाना और विभिन्न प्रयोजनों के लिए उसकी पूर्व सेवा की गणना तथा धारणाधिकार/वर्गीकरण का प्रयत्न भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इन निमित्त जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

10. भर्ती नियमों का संशोधन:—केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों (समूह "क" और "ख") पर व्यक्तियों को भर्ती की विनियमित करने वाले सभी नियम उस विस्तार तक संशोधित किए गए समझे जाएंगे जो इन नियमों में उपबंधित हैं।

11. समूह "क" और "ख" सेवाओं/पदों पर अधिशिष्ट कर्मचारियों की पूर्व नियुक्तियों का विधिप्राप्तकरण— अधिशिष्ट कर्मचारियों की केंद्रीय सरकार के विभागों/कार्यालयों/संगठनों में समूह "क" और "ख" सेवाओं/पदों पर भूतपूर्व गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञान संख्या 1/2/68-सी. सी. /सी. एस. (iii) तारीख 25 मार्च, 1988 के उपबंधों के अनुसार इन नियमों के प्रारंभ से पहले की गई सभी नियुक्तियाँ इस प्रकार वैध रूप से की गई समझे जाएंगी मानो ये नियम सभी सुसंगत समयों पर प्रवृत्त थे।

[सं. 2/39/85 से. से. (iii)]

ए. एस. तनेजा, उप सचिव

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 19th December, 1986

### NOTIFICATION

G.S.R. 1296(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules for regulating the redeployment of surplus staff against vacancies in the Central Civil Services and Posts (Group 'A' and 'B') namely:—

1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Redeployment of Surplus Staff against vacancies in the Central Civil Services and Posts (Group 'A' and 'B') Rules, 1986. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions: In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Cell" means the Central (Surplus Staff) Cell in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions;

(b) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(c) "Surplus Staff" and "Surplus Employees" means the Central Civil Servants (other than those employed on ad-hoc, casual, work-charged or contract basis) who have been rendered surplus from the various Ministries/Departments/Offices of the Government of India (other than the Ministry of Railways excluding the establishment of the Headquarters of the Railway Board and the lower field formations of the Ministry of Defence other than the Defence Research and Development Organisation) as a result of (i) introduction of administrative reforms;

(ii) studies by the Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance;

(iii) Studies of work measurement or administrative reforms undertaken by Government Departments or offices; and

(iv) abolition or winding up of permanent or long-term organisations of the Central Government;

Provided that in the case of the employee of an organisation set up temporarily for a specified purpose, they shall be treated as surplus staff or surplus employees for the purposes of this rule only if the organisation has been in existence for a period exceeding 15 years and, they have rendered not less than 5 years' continuous service in that organisation.

3. Redeployment of surplus staff through the Commission: (1) The controlling authority in respect of a Group 'A' or Group 'B' Service/post in which any vacancy is to be filled up by direct recruitment through the Commission (otherwise than on the basis of a competitive examination) shall while sending requisition for the purpose to the Commission, also simultaneously send a copy thereof to the Cell.

(2) (i) The Commission shall not entertain a requisition placed for the purpose unless it indicates that a copy thereof has simultaneously been sent to the Cell and shall take action for recruitment to the posts notified to the Commission in the usual manner only if—

(a) no recommendation is received by it from the Cell, within a period of 15 days from the date of receipt of the requisition in its offices, sponsoring the surplus employee(s) for appointment against such vacancy or vacancies, or

(b) the candidate recommended for consideration by the Cell is not found suitable by the Commission for appointment to the post in question.

(ii) The Commission may consider any surplus employee whose bio-data has been referred to it by the Cell, for appointment to post, even if he has not been specifically recommended by the Cell for that post:

Provided that the post in question carries the same scale of pay or has the same maximum of the pay scale as the one held by him; he is found suitable for appointment to such post in preference to the other posts for which his candidature may have been sponsored by the Cell; and he does not suffer from any of the disabilities mentioned in clause (c) of sub-rule (5) of this rule.

(3) Where a post is to be filled up by transfer in consultation with the Commission the controlling authority in respect of the post shall first intimate the vacancy to the Cell, who, if it has a surplus employee, on its rolls who is prima-facie suitable for appointment thereto, shall sponsor him to the commission, under intimation to the controlling authority concerned, for being considered for absorption against the post in question. Such a post will be circulated only if (a) the Cell communicates the non-availability of a suitable surplus employee from its rolls to sponsor for absorption in it, or (b) the Commission holds the surplus employee sponsored by the Cell to be unsuitable for appointment to the post.

(4) The surplus employees recommended by the Cell will be entitled to first priority for appointment to the vacancies in Group 'A' and 'B' Services/Posts filled by direct recruitment through the Commission (otherwise than on the basis of a competitive examination held by the Commission) or by transfer :

Provided that they are found suitable by the Commission and no suitable disabled defence services personnel are available with them for appointment to such vacancies.

(5) (a) The Cell shall recommend to the Commission the name of a surplus employee, who for the time being is borne on its rolls, for being considered for appointment to a specific post, the vacancy wherein has been notified to the Commission and to the Cell, and for appointment to which the surplus employee concerned appears to the Cell to be prima facie suitable, having regard to the scale of pay attached to the post and the one held by him, his qualifications and the relevance of his previous experience;

(b) The Cell may recommend more than one surplus employee on its rolls for being considered for appointment to a post for which each of them seems to it to be prima-facie suitable for appointment;

(c) The Cell shall not recommend the name of a surplus employee to the Commission:

(i) if on being sponsored by the Cell he has already been recommended by the Commission for appointment to a post in a Central Government Department, carrying a pay-scale not lower than his existing pay-scale;



(ii) if he has completed six months stay on the rolls of the Cell; or has joined another post in the meantime whether on re-deployment through the Cell, or otherwise, or has asked for reversion to another continuing post on which he holds a lien;

(iii) if he is due for superannuation within six months from the date of his transfer to the rolls of the Cell;

(iv) if his services are terminated or he is to be retired (including inter alia on a notice seeking premature voluntary retirement given by the surplus employee) or discharged from service or otherwise ceases to be on the rolls of the Cell on any date before the expiry of six months from the date of his transfer to the rolls of the Cell;

(v) for absorption in a post which lies outside the parameters of placement laid down in rule 5.

(6) Determination of suitability of a surplus employee and relaxation of qualifications, experience, etc. for this purpose.—(a) The Commission may, at its discretion consult the confidential reports written earlier on a surplus employee or, if necessary, call him for interview to determine his suitability for appointment to a post but shall not subject him to a written test for this purpose.

(b) The Commission may, in its discretion, relax the educational qualifications, experience etc. prescribed for recruitment to a service/post, in respect of any member of the surplus staff sponsored by the Cell for appointment to such service/post, if the surplus candidate is otherwise considered by them to be suitable for appointment to the service/post in question.

(c) The Commission shall, as far as possible, finalise and communicate to the Cell its assessment of suitability or otherwise of a surplus employee recommended by the Cell for a post, within one month from the date of receipt of such recommendation in its office.

"Explanation : For the purpose of these rules, a surplus employee shall be deemed as transferred to borne on the rolls of the Cell for the purpose of arranging his redeployment from the date from which he has been declared surplus by his parent Ministry/Department in the contingencies specified in clause (c) of rule 2 above, even though he is formally not so transferred and only his particulars have been reported to the Cell".

4. Redeployment in posts not filled through the Commission : (1) All vacancies in Central Civil Services and posts in Groups 'A' and 'B' which are to be filled in by direct recruitment or by transfer, but otherwise than through the Commission, shall be filled up from amongst the surplus staff, unless the controlling authority of the service/post in question has ascertained from the Cell that they have no suitable persons from amongst the surplus staff available with them for being nominated against the particular post.

(2) The provision made in sub-rule (1) shall not apply to the posts and services under the administrative control of—

(a) the Department of (i) Atomic Energy (ii) Space (iii) Electronics (iv) Indian Audit & Accounts and (v) Railways (excluding the posts located in the Headquarters offices of the Railway Board);

(b) the Ministry of Defence (lower field formations other than the Defence Research and Development Organisation);

(c) the various security and para-military organisations under the Ministries of Home Affairs and Defence :

Provided that this will not debar the controlling authority of such services/posts to request the Cell to sponsor suitable surplus employees, and to appoint them.

(3) In respect of the surplus employees nominated under sub-rule (1) the Department of Personnel and Training, and in respect of those sponsored under sub-rule (2) the Ministry/Department/Organisation concerned, shall determine their suitability for appointment to the posts concerned, where necessary, by relaxation of the educational qualifications, experience, etc., prescribed under the relevant recruitment rules.

5. Determination of placement.—(a) (i) As far as possible, a surplus employee shall, subject to his suitability, be redeployed in a post carrying a pay-scale matching his current pay scale.

(ii) For the purpose of clause (i), a matching pay-scale shall mean a pay-scale the maximum of which is equal to that of the pay-scale of the surplus employee, and the minimum of which is not higher than the basic pay (including the stagnation pay) which the surplus employee is in receipt of at the time of making his nomination.

(b) Where a suitable vacancy in a post carrying matching scale of pay is not available, the surplus employee may be redeployed in a post carrying a non-matching pay scale :

Provided that—

(i) the maximum of the pay scale of such post does not exceed the maximum of the pay-scale of the surplus employee by more than 10 per cent; and

(ii) such post is not lower than the post which forms, or would or dinarily form, the next lower rung in the promotional ladder for the incumbents of the post of the level currently held by the surplus employee :

Provided further that when redeployed in a post carrying a lower scale of pay, the surplus employee shall be permitted to carry his previous pay-scale along with him to the next post even if he was only officiating in it.

6. Age limit.—The upper age limit shall not apply in the case of a surplus employee appointed under these rules.

7. Medical Examination.—The surplus staff redeployed by the Cell shall not be required to undergo fresh medical examination unless different medical

standards have been prescribed for the post in the recipient organisation or unless the person concerned had not been medically examined in respect of his previous post or, if examined, had been declared medically unfit.

8. Acceptance of the surplus staff recommended for appointment by the Commission or nominated by the Cell.—The administrative Ministry/Department shall, on receipt of the recommendation made by the Commission or nomination made by the Cell, for appointment of a surplus employee to a post/service for which a requisition had earlier been placed upon the Commission or the Cell, as the case may be, shall take immediate action to issue the orders of appointment of the surplus employee concerned under advice to the Cell and, where relevant, the Commission.

9. Fixation of pay and seniority, counting of previous service for various other purposes and carrying over of lien/classification.—The fixation of seniority and pay of the surplus employee and counting of his previous service for various purposes and carrying over of lien/classification in the new post to which he

is appointed on redeployment under these rules shall be regulated in accordance with the instructions issued from time to time by the Government of India in this behalf.

10. Amendment of recruitment rules.—All rules regulating the recruitment of persons to the Central Civil Services and posts (Group 'A' and 'B') shall be deemed to have been amended to the extent as provided for in these rules.

11. Validation of earlier appointments of surplus employees in Group 'A' and 'B' services/posts.—All appointments made of surplus employees in Group 'A' and 'B' services/posts in Central Government Departments/Offices/Organisations before the commencement of these rules in accordance with the provisions of the (then) Ministry of Home Affairs O.M. No. 1/2/66-CC/CS. III dated the 25th March, 1968, shall be deemed to have been validly made as if these rules were in force at all relevant times.

[No. 2/38/85 CS. III]

A. S. TANEJA, Dy. Secy.